भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3302

20 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

अर्बन चैलेंज फंड

3302. श्री टी. एम. सेल्वागणपतिः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का शहरों के विकास केन्द्रों के रूप में शहरों के सृजनात्मक पुनर्विकास तथा जल एवं स्वच्छता सुविधाओं के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए एक लाख करोड़ रुपए के अर्बन चैलेंज फंड की स्थापना करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का मूलभूत भू-स्थानिक अवसंरचना और आंकड़ों के विकास के लिए राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन की स्थापना करने का भी विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त मिलन से भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण, शहरी नियोजन और अवसंरचना परियोजनाओं के डिजाइन में सुविधा होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) शहरी अवसंरचना क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, बजट 2025-26 में सरकार ने 'विकास केंद्रों के रूप में शहर', 'शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास' और 'जल एवं स्वच्छता' के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के शहरी चुनौती कोष की स्थापना की घोषणा की है।

यह कोष बैंक योग्य परियोजनाओं की लागत के 25 प्रतिशत तक का वित्तपोषण इस शर्त के साथ करता है, कि लागत का कम से कम 50 प्रतिशत बांड, बैंक ऋण और सार्वजनिक निजी भागीदारी से वित्तपोषित किया जाएगा।

(ख) से (घ) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सूचित किया है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में आधारभूत भू-स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए के

परिव्यय के साथ राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन की घोषणा की गई है। डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम) मजबूत भू-स्थानिक अवसंरचना के निर्माण के घटकों में से एक है। यह राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति, 2022 के अनुरूप है, जिसमें उच्च-रिज़ॉल्यूशन स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और मानचित्रण प्रणाली और उच्च सटीकता डीईएम विकसित करने की परिकल्पना की गई है।

*****